हाल के कृषि कानूनों की समीक्षा: संभावनाएं और चुनौतियां

प्रवीण कुमार, प्रियंका कुमारी एवं रिषभ कुमार दीदावत

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली

परिचय

भारत की एक विशाल आबादी है, जिसमें से लगभग 55% कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। हाल के दिनों में जरूरतों के बदलते परिदृश्य के कारण कृषि क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। लेकिन इस प्राथमिक क्षेत्र की जमीनी स्थिति में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ है। भारत में दुर्घटना मृत्यु और आत्महत्याएं 2019 शीर्षक वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रकाशन के अनुसार, 2019 में 10281 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जो कृषि क्षेत्र में विभिन्न संकट स्थितियों का सामना कर रहे हैं। जहां तक किसानों की आय पर विचार किया जाता है, किसानों और गैर-कृषि श्रमिकों के बीच सापेक्ष आय में एक बड़ा अंतर है|

Fig. 1.2: Ratio of income per non agriculture worker to income per cultivator

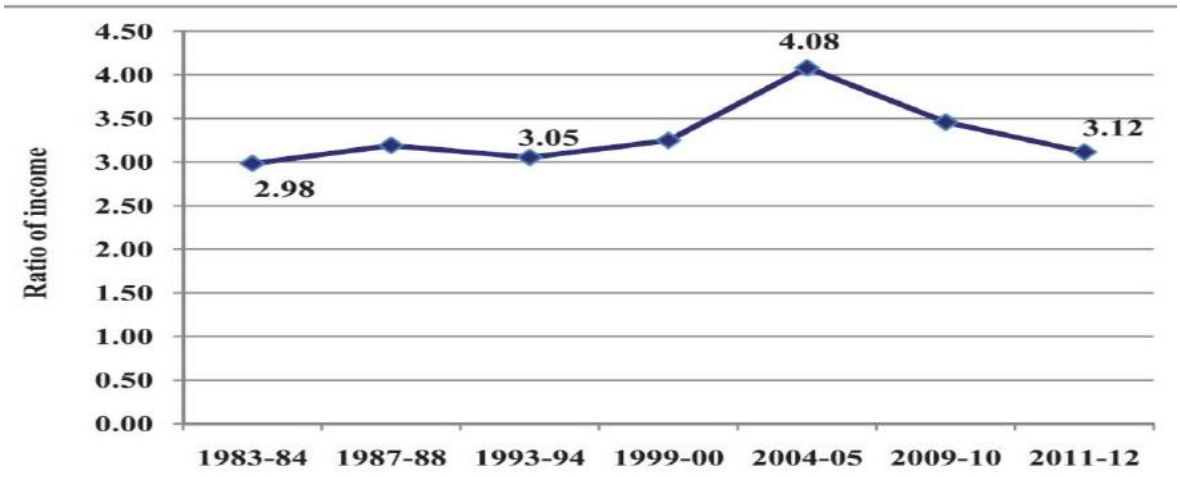

e-ISSN No. 2583-0937

बाजार की स्थितियां भी बदलने के लिए अपवाद नहीं हैं, हमारे बाजारों में घरेलू उत्पादन की कुल मांग कम हो गई है जिससे घरेलू कीमतों को बहुत कम गिरने से रोकने के लिए बड़ी मात्रा में निर्यात की आवश्यकता हो रही है। हमारे पास क्रमशः 60 मिलियन टन चीनी, चावल और गेहूं 72 मिलियन टन का अतिरिक्त बफर स्टॉक है, जो राजकोषीय संसाधनों की भारी निकासी का कारण बनता है। यहां तक कि आयात भी अधिक आकर्षक हो रहे हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों की तुलना में काफी कम हैं। भारत सरकार ने 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने का इरादा किया है। इसलिए, भारतीय कृषि को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ, भारत सरकार ने हाल ही में तीन कानून (किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, पारित किया है। 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का किसान (अधिकारिता और संरक्षण) समझौता। इन विधेयकों के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना है, लेकिन जमीनी स्थितियों पर विचार करने के बाद परिणाम अच्छा नहीं दिखता है। कृषि बाजार पर बिल किसानों को एपीएमसी 'मंडियों' के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है, जिसे भी वे बेचना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा और परिवहन पर लागत में कटौती के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। हालांकि, इस विधेयक का मतलब यह हो सकता है कि राज्य 'कमीशन' और मंडी शुल्क खो देंगे ' जो राज्य अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। अनुबंध खेती पर कानून किसानों को कृषि व्यवसाय फर्मों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ उनकी उपज की पूर्व-सहमत कीमतों पर अनुबंध में प्रवेश करने की अनुमति देगा। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने का प्रयास करता है। यह असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर स्टॉक-होल्डिंग सीमा को लागू करना समाप्त कर देगा।

नए कृषि कानूनों पर विभिन्न हितधारकों के विचार

सरकार ने नए कृषि कानूनों के संबंध में विरोध करने वाले किसानों की मांगों के प्रति कई तर्क दिए हैं जो इस प्रकार हैं:

1. एमएसपी कभी कानून नहीं था, केवल एक नीति थी; कानून के जरिए एमएसपी को गारंटी देने की मांग अनुचित है।
2. किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह कृषि में बाजार के उतार-चढ़ाव का सभी को पालन करना चाहिए।
3. अनुबंध खेती से छोटे किसानों को उनके छोटे-छोटे भूखंडों से मुक्त कराने में ही मदद मिलेगी और वे बाहर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन अनुबंध खेती पर सरकार के दृष्टिकोण को सही मानते हुए हम अनुबंध खेती के साथ किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में वास्तविक दृष्टिकोण खो देते हैं।

नए कृषि कानूनों पर किसानों का अपना पक्ष है, उन्होंने अपने तर्क इस प्रकार बताए:

हरियाणा और पंजाब के बिचौलियों के संबंध में किसान आढ़तियों को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि जीवन रेखा के रूप में देखते हैं।

1. अनुबंध खेती के संबंध में, छोटे किसानों ने तर्क दिया कि बड़े ठेकेदार आसानी से अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकर जाएंगे और या तो उत्पादों को खरीदने से इनकार कर देंगे या एक बार कटाई हो जाने के बाद कीमत कम कर देंगे उदाहरण के लिए पंजाब में पेप्सिको अनुबंध खेती का अनुभव और यदि वे अपनी जमीन देते हैं यदि अनुबंध सिर्फ एक वर्ष के लिए है और सालाना नवीकरणीय है तो कोई ठेकेदार भूमि में निवेश नहीं करेगा, तो वे उन्हें वापस नहीं ले सकते। किसान इन कृषि कानूनों को एपीएमसी

e-ISSN No. 2583-0937

मंडियों की तुलना में निजी क्षेत्र, कॉर्पोरेट क्षेत्र को अनुचित लाभ प्रदान करके उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा की प्रकृति को कम करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। किसानों के साथ एक धारणा यह है कि; वे उस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार करते हैं जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों से अधिक होती हैं, वे देश के बाहर बेचने में सक्षम नहीं होने पर नाराज होते हैं, उदाहरण के लिए, प्याज और चीनी।

राज्यों की भूमिका

राज्य बढ़ती आबादी को खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि अधिकांश खाद्यान्न सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों से आते हैं। एनएफएसए (लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों) और पीडीएस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीद कीमतों के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद भारत सरकार के लिए एक दायित्व है क्योंकि पीडीएस, एनएफएसए के अन्तर्गत एक कानूनी और अधिकार-आधारित अधिकार है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को अनसुना नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि लगभग 80% धान और 70% गेहूं उत्पादन इन राज्यों से खरीदा जाता है और केवल 44% चावल उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से गेहूं खरीद में केवल 23% का योगदान दिया है (खाद्यान्न बुलेटिन और कृषि सांख्यिकी एक नज़र में, 2017-2019)। इसलिए इन नए कृषि कानूनों के माध्यम से खरीद प्रणाली को खत्म करना किसी के हित में नहीं है। इसलिए, इन कानूनों के पारित पारित होते ही यह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कानूनी लड़ाई का आधार बन जाएगा क्योंकि राज्य इसे अपने अधिकारों का अतिक्रमण समझेंगे, क्योंकि केंद्र ने इन कानूनों को कृषि मंत्रियों और राज्यों के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा किये बिना ही पारित किया है, यहां तक कि संविधान में कृषि का उल्लेख राज्य सूची में भी किया गया है।

इन कानूनों का प्रभाव

वास्तविक मुद्दा अधिकांश कृषि वस्तुओं के लिए लाभकारी कीमतों की कमी है और समस्या का एक हिस्सा वर्तमान कृषि की प्रकृति बदल रहा है (बाजारों पर बढ़ती निर्भरता, कृषि अर्थव्यवस्था के बढ़ते मुद्रीकरण के साथ-साथ मशीनीकरण में वृद्धि) । इस एक अप्रत्याशित और मनमानी सरकारी नीति व्यवस्था से स्थिति बदलने की संभावना नहीं है। इन कृषि कानूनों का किसानों और बाजारों पर नकारात्मक और साथ ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एफपीटीसी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार किसान अपनी उपज को एपीएमसी के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं । लेकिन पहले के आंकड़ों से पता चला है कि धान और गेहूं के लिए भी केवल 29% और 44% फसल ही मंडी में बेची जाती है, जबकि 49% और 36% स्थानीय निजी व्यापारी या इनपुट डीलर को बेची जाती है। भारत में मंडियों की कमी के कारण (2019 में 6630) जैसा कि कृषि पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुशंसित कम से कम 41000 होना चाहिए, किसान मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हैं और परिवहन लागत को वहन करने में असमर्थता के कारण वे मंडी नही पहुँच पाते हैं | यहां तक कि 18 राज्यों ने एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों की स्थापना की अनुमति दी है, 19 राज्यों ने किसानों से कृषि उपज की सीधी खरीद की अनुमति दी है और 13 राज्यों ने क्रमशः एपीएमसी के बाहर किसान बाजार की स्थापना की अनुमति दी है। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण नए स्थापित निजी बाजारों में संग्रह केंद्र खोलने और वेतन, ग्रेडिंग, भंडारण और परिवहन की लागत अधिक होगी और वस्तुओं के खराब होने के जोखिम के कारण खुदरा श्रृंखलाएं सीधे किसानों से खरीदने की तुलना मे मंडी से खरीदना पसंद करती हैं। यदि नए निजी बाजारों की स्थापना, परिवहन लागत का आकार मंडी कर से

e-ISSN No. 2583-0937

अधिक है तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं होगा कि किसानो को निजी बाजारों में उच्च मूल्य प्राप्त होंगे।

ये सभी बिल कृषि व्यापार के रूप को डिजिटल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसानों की ओर से कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी के कारण, वे बिचौलियों के जाल में पड़ जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनके लिए परिचालन लागत में वृद्धि होगी। अनुबंध खेती के संबंध में एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि बड़ी कॉर्पोरेट फर्मों और व्यापारिक ठेकेदारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, जब भी किसान ठेकेदार से अलग करना चाहते हैं, तो उन्हें वकीलों को मोटी फीस देनी पड़ती है या तो उनके शोषण के लिए द्वार खुल जाते हैं। संविदा कृषि अधिनियम में भी, किसान और ठेका फर्म के बीच निर्धारित पारस्परिक रूप से स्वीकार्य गुणवत्ता, ग्रेड और मानक (तीसरी एजेंसी द्वारा जांच के प्रावधान) को पूरा करने की संभावना कम है, इससे किसानों का शोषण हो सकता है जो अति प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अत्यधिक फसल और कीटनाशकों या कीटनाशकों के माध्यम से उपलब्ध भूमि भूमि को बंजर बनने के लिए और अधिक संकटग्रस्त बना रही है। जहां तक किसानों के अधिकारों का सवाल है, उन्हें विभिन्न पक्षों के बीच विवाद समाधान के संबंध में अपील का कोई प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है और राज्यों के निर्णयों को चुनौतियों से मुक्त करने के लिए भी प्रदान नहीं किया गया है। जब इन कृषि कानूनों में किसान की परिभाषा पर विचार किया जाता है तो अनौपचारिक रूप से खेती के लिए लीज पर जमीन लेने वाले खेतिहर मजदूरों और जोतने वालों को बाहर करने के लिए कहा जाता है, किसानों के एक बड़े हिस्से को छोड़कर उन पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान कहीं न कहीं फायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि पिछले अधिनियम में कुछ कृषि वस्तुओं की भारी खरीद में एक सीमा थी जो निवेश करने के लिए निजी निवेश व्यवस्था में बाधा थी। पिछले कानून के कुछ प्रावधानों के परिणामस्वरूप बिचौलियों के लिए एक ग्रे मार्केट का निर्माण हुआ जो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे खाद्यान्नों की बड़ी बर्बादी को रोकने के लिए भंडारण के बुनियादी ढांचे में एक अच्छे निवेश की आवश्यकता है जो इस संशोधित कानून के माध्यम से पूरा होता प्रतीत होता है। ये कानून वस्तुओं के निर्यात पर सभी प्रतिबंधों को हटाते हैं जो किसानों और अन्य हितधारकों के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। इस बीच, इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं जिसमें वस्तुओं की जमाखोरी शामिल है जो अंततः मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है।

एक मजबूत नीति बैक अप की आवश्यकता

एमएसपी- प्रोक्योरमेंट सिस्टम और एपीएमसी के मुख्य मुद्दे को संबोधित करने के अलावा, एक नियामक तंत्र की अनुपस्थिति और पारदर्शिता की कमी दो प्रमुख सीमाएं हैं। मौजूदा नीतिगत ढांचा जिसमें मुद्रास्फीति प्रबंधन और राजकोषीय घाटे के प्रति जुनून पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, सरकार से या तो मूल्य स्थिरीकरण या राजकोषीय खर्च के माध्यम से खेती की लागत में कमी के समर्थन में कमी की संभावना है। कृषि और एकीकृत गैर-कृषि क्षेत्र के विविधीकरण की चुनौतियों को पहचानने के लिए कृषि क्षेत्र को एक व्यापक नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगे का रास्ता उनकी उपज की बिक्री के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के माध्यम से है; आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं का विकास; कृषि और कृषि का एक नेटवर्क विकसित करना। इनपुट उद्योग; उच्च तकनीक कृषि; मूल्य संवर्धन; ग्रामीण आर्थिक पुनरोद्धार के एक हिस्से के रूप में बिचौलियों को शामिल किए बिना उपभोक्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन और उत्पादकों की एक कड़ी विकसित करने के साथ निर्यात और प्रसंस्करण।

e-ISSN No. 2583-0937

किसानों के लिए सुझाव

एपीएमसी और एमएसपी की सहायता से हरियाणा और पंजाब के किसान मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसने भूजल भंडार में कमी के साथ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की मिट्टी को लूट लिया है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि 1973 और 2001 के बीच गेहूं और चावल चक्र के कारण भूजल तालिका में हर साल लगभग 3 फीट की गिरावट मध्य पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 2000 और 2006 के बीच पांच गुना तेज हो गई है। इसलिए विशेष रूप से इन क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की आवश्यकता है जैसा कि 1986 की एस.एस. जोहल रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित है, आय में सुधार की पर्याप्त संभावनाएं हैं क्योंकि गेहूं और चावल सहित 23 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की जाती है और यदि किसान चावल की खेती छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों को बचाने के लिए SRI (सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन) जैसी खेती के तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

चूंकि इन हाल ही में पारित कानूनों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में योगदान करना है, लेकिन किसानों और भूमि से जुड़ी जमीनी हकीकत उतनी उपयुक्त नहीं है क्योंकि ज्यादातर हमारे किसान छोटे और सीमांत हैं जिनके पास कई संसाधनों की कमी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि का विखंडन एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रति व्यक्ति कम भूमि उपलब्धता के लिए जिम्मेदार है। हमारे किसानों के ज्ञान और विशेषज्ञता पर विचार करते समय उन्हें ज्यादातर बाजार लेनदेन (बिक्री, ग्रेडिंग, बाजार की जानकारी आदि) के लिए एक बिचौलिए की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी प्रकार के बाजार लेनदेन के लिए बिचौलियों की भूमिका को हटाने के लिए नए कृषि कानूनों का उद्देश्य अप्रत्याशित रहता है। . अनुबंध कृषि कानून के साथ भी यही सोच है, किसानों के बीच कम प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता को देखते हुए कोई भी ठेका देने वाली फर्म कम भूमि और समय (वार्षिक अनुबंध) के लिए नहीं जाएगी। अंत में, संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को देखते हुए, भंडारण बुनियादी ढांचे और कोल्ड स्टोरेज में निजी निवेश का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने का एक मौका है, लेकिन इस कानून के नकारात्मक पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर जमाखोरी में योगदान कर सकता है। बाजार में मुद्रास्फीति के लिए। कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश के माध्यम से समग्र स्थिति में सुधार किया जा सकता है, इस क्षेत्र के द्वार सभी के लिए खोल दिए जा सकते हैं।